(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज की अनुमानित मांग कितनी थी और इसका कितना उत्पादन हुआ था ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कागज का मूल्य कितना है ; और

(घ) देश में कागज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान कागज का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टन)
1989 . .	18.50
1990 . .	19.56
1991 . .	19.65

इस समय, देश सामान्य प्रकार के कागज की अपेक्षाएं पूरी करने में आत्मनिर्भर है। केवल विशेष प्रकार के कागज का सीमित मात्रा में आयात किया जा रहा है।

(ग) कागज उद्योग में विभिन्न एकक विभिन्न प्रकार के कागज और गत्ते का उत्पादन करते हैं और इनकी कीमतें हर मिल और हर क्षेत्र में अलग-अलग होती हैं।

(घ) (i) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कम सीमा शुल्क की दर पर लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात करने की अनुमति दे दी गयी है।

(ii) लिखाई और छपाई के कागज तथा बिना लेप के क्राफ्ट कागज जिसमें जूट (जूट की रद्दी), पेस्टा अथवा खोई अथवा इनके मिश्रण अथवा उपर्युक्त सामग्रियों की दो या तीन लुगदियों के मिश्रण से बनी लुगदी का वजन 75 से कम न हो, के निर्माण को उत्पादन शुल्क से छूट है।

(iii) कृषि अपशेषों तथा अन्य अपरंपरागत कच्चे माल का न्यूनतम 50% तक प्रयोग करने वाली कागज मिलों से रियायती दरों पर उत्पाद शुल्क लिया जाता है।

(iv) खोई, कृषि अपशेषों तथा अन्य अपरंपरागत कच्चे माल से बनी न्यूनतम 75% लुगदी का प्रयोग करने वाले कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट दी गयी है।

Technology upgradation and R and D efforts by Department of Heavy Industry

4719. DR. SANJAYA SINH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what steps have been taken by each of the public sector undertakings under the Department of Heavy Industry for technology upgradation and R&D efforts and also for import substitution during the last three years, with year-wise details; and

(b) whether collaborations with international organisations have been entered into by these Public Sector Undertakings during the same period for setting up research facilities; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.